

शिक्षा के बदलते स्वरूप में कला एवं तकनीकी की भूमिका

आनन्द कुमार सिंह*

शिक्षा किसी व्यक्ति के जन्म लेने के बाद उसे मिलने वाला संभवतः सबसे पहला अनुभव होता है। हर बच्चा पारिवारिक माहौल, सामाजिक-आर्थिक स्तर, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय इत्यादि से सीखता है। कला एवं तकनीकी विकास के साथ शिक्षा के प्रसार का तरीका तथा साथ ही साथ नई तकनीक आधारित पठन-पाठन के प्रति दुनिया का नज़रिया भी बदला है। आज छोटे-छोटे बच्चे, माता-पिता, नाना-नानी एवं दादा-दादी के साथ खेलने या बातचीत करने के बजाय मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलने के लिए बेचैन रहते हैं। आज जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्मार्ट-क्लासेज़ होती हैं, कॉलेज जाता है तो ऑडियो-विज़ुअल कोर्सेस और यूनिवर्सिटी में आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस से लैस उपकरणों इत्यादि से उसका सामना होता है। इंटरनेट और तकनीकी उन्नति ने आज 21वीं सदी की शिक्षा और उसके प्रसार का तरीका बदल दिया है। यह लेख शिक्षा के इसी निरंतर बदलते प्रारूप और उसमें कला एवं तकनीकी की भूमिका का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है।

शिक्षा का इतिहास दुनिया में मानवजाति के इतिहास जितना ही पुराना माना जा सकता है और इसके विकास में कला का प्रमुख योगदान रहा है। प्राचीनतम स्रोतों में हम गुफ़ाओं की दीवारों और छतों पर उकेरे गए चित्रों और आकृतियों से अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते रहे होंगे। पाषाण युग से अब तक मानवजाति नित नए प्रयोग और आविष्कार करती आ रही है जो शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रतिबिंबित होते रहे हैं। आख़िर गुफ़ाओं की दीवारों से लेकर शिलालेखों और फिर ताम्रपत्रों से लेकर डिजिटल टेबलेट्स तक का सफ़र आसान नहीं रहा है। भारत वर्ष की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन

सभ्यता है, अतः भारतवर्ष में शिक्षा का इतिहास और विकास का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

भारतीय शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ, संस्थान आधारित इतिहास के संदर्भ में, वैदिक युग (लगभग 1500 ई.पू. से 500 ई.) से माना जाता है। वैदिक युग में शिक्षा के लिए भारतवर्ष में गुरुकुल परंपरा के साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों का भी निर्माण हुआ जिनमें तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला अध्ययन-अध्यापन के प्रमुख केंद्र रहे। इसी काल में हमारे प्राचीन ग्रंथ, जैसे— वेद, उपनिषद, पुराण, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामसूत्र इत्यादि भी लिखे गए। सातवीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य

तक भारत ने बहुत-से बाहरी और आंतरिक आक्रमणों को झेला और इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकतर सुल्तानों, मुगल साम्राज्य और उनके बाद अंग्रेजों का वर्चस्व रहा। ऐसी राजनैतिक हलचल के मध्य शिक्षा व्यवस्था को स्वाभाविक रूप से बहुत नुकसान पहुँचा। हालाँकि, सुल्तानों और मुगल बादशाहों तथा उनके दरबारियों ने भी बहुत-से शिक्षण संस्थान बनवाए, फिर भी पुराने शैक्षणिक संस्थानों और व्यवस्था को पहुँची क्षति पूर्ण न हो सकी। मुगलों के पश्चात् अंग्रेजों की औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था ने रही-सही कसर भी पूरी कर दी। वे भारतीयों को ज्ञान तो देना चाहते थे, परंतु केवल उतना जिससे वे अंग्रेजों के काम आ सकें और उनकी गुलामी के खिलाफ़ आवाज़ ना उठाएँ। लेकिन फिर भी भारतीय समाज-सुधारकों, शिक्षाविदों और विचारकों, जैसे— राजा राम मोहन राय, रवींद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता, महात्मा गांधी, श्री अरबिंद घोष, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. अबुल कलाम आज़ाद आदि द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था के पुनर्जागरण के प्रयासों से अंग्रेजी साम्राज्य विफल हुआ। साथ ही, भारत ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता भी प्राप्त की। एक बड़ी चुनौती को परास्त करने के बाद अब उतनी ही बड़ी चुनौती भारतीय शिक्षा के सामने खड़ी थी, क्योंकि अब तक अंग्रेजों द्वारा बनाई गई शिक्षा व्यवस्था भारत की संस्कृति को नुकसान पहुँचा चुकी थी। इस चुनौती से सामना करने का बीड़ा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सक्षम नेतृत्व में, स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्रालय ने उठाया जिसे आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय शिक्षा व्यवस्था
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने देश में शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत-से प्रयास किए। विभिन्न शिक्षण संस्थान सृजित करने के साथ-साथ विभिन्न योजनाएँ व नीतियाँ बनाई गईं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें समय-समय पर संशोधित भी किया गया जिससे भारत के घर-घर तक एवं जन-जन तक शिक्षा की ज्योति पहुँचाई जा सके। स्वराज के प्रारंभिक दशक में भारत सरकार द्वारा गठित संस्थानों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (1945), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (1953), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (1961) और राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा, 1962) प्रमुख रहें। इन संस्थानों के संगठन के बाद भारत सरकार ने विभिन्न योजनाएँ पारित कीं, जिनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 का स्थान विशिष्ट है। सर्वप्रथम इसे 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उद्घाटित किया गया था। सन् 1986 में इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा अद्यतित किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं व अति पिछड़े तबकों तक समान रूप से शिक्षा पहुँचाना था। उसके बाद से ही देश के शैक्षिक संस्थानों में तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्सों में प्रवेश के लिए समान प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलावा सरकार द्वारा विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (1975) बनाई गई। इसे वर्ष 1988, 2000 और फिर 2005 में अद्यतित किया गया। 'राष्ट्रीय साक्षरता अभियान'

(1988) और 'सर्व शिक्षा अभियान' (2000-01) स्कूल न पहुँच पाने वाले बच्चों तक पहुँच तो बना रहे थे, लेकिन उसको शक्ति मिली वर्ष 2009 में, संसद से पारित हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 से, जिसने देश के सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया।

सिनेमा में शिक्षा और शिक्षा में सिनेमा

यूँ तो भारत में सिनेमा 20वीं सदी के आरंभ में ही आ चुका था, हालाँकि साधारण जनमानस तक पहुँचने में उसे दशकों का समय लग गया। फिर भी सिनेमा लोगों तक पहुँचा (1940 के शुरुआती दशक में) और पहुँचते ही कौतूहल का विषय बन गया। रेडियो (AIR, 1936 में) की शुरुआत के बाद सिनेमा सर्वसाधारण के बीच मनोरंजन का दूसरा और धीरे-धीरे सबसे पसंदीदा साधन बन गया। सन् 1959 में दूरदर्शन के प्रसारण के साथ ही लोगों के घरों में टी.वी. ने भी स्थान बना लिया। दूरदर्शन ने धार्मिक, ऐतिहासिक कार्यक्रमों द्वारा लोगों का मनोरंजन करना शुरू किया और समय के साथ-साथ शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण भी प्रारंभ हो गए। सिनेमा भी अभी इसी मार्ग पर अग्रसर हो चला है। धीरे-धीरे सिनेमा और टी.वी., दोनों मनोरंजन के साथ-साथ लोगों को जागरूक और शिक्षित करने में लग गए।

सामान्यतः यह कहा जाता है कि फ़िल्में समाज का आइना होती हैं। अतः भारतीय फ़िल्म निर्माताओं ने बहुत-सी शैक्षणिक-मनोरंजक फ़िल्मों का भी निर्माण किया। जिससे लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो सकें और वहीं शिक्षक/शिक्षिकाएँ पढ़ाई की

नई-नई विधाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर केंद्रित इन फ़िल्मों में, *जाग्रति* (1954), *श्री 420* (1955), *दीदी* (1959), *जो जीता वही सिकंदर* (1992), *स्वदेस* (2004), *तारे ज़मीन पर* (2007), *स्टैनली का डब्बा* (2011) *चिल्लर पार्टी* (2011), *निल बटे सन्नाटा* (2016), *हिंदी मीडियम* (2017), *हिचकी* (2018), *नोटबुक* (2019) और *सुपर 30* (2019) प्रमुख हैं। इन फ़िल्मों की कहानियाँ स्कूल-कॉलेजों में, विद्यार्थियों के जीवन, उनके संघर्षों, सहपाठियों-शिक्षकों/शिक्षिकाओं-अभिभावकों के साथ उनके पारस्परिक संबंधों, समाज का उनके प्रति व्यवहार, समाज के प्रति विद्यार्थियों का नज़रिया इत्यादि साधारण से लगने वाले, लेकिन गंभीर मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। छोटे-छोटे बच्चों पर शिक्षा-प्रणाली के दबाव और उससे हार कर गलत रास्तों पर चले जाने या मानसिक प्रताड़ना संबंधी विषयों को मार्मिक व संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में, वर्ष 2018-2019 में, 'हैप्पीनेस करिकुलम' लागू करना विशेष उल्लेखनीय है, लेकिन हमें इसका विश्लेषण भी करना होगा कि आखिर ऐसी स्थिति बनी क्यों और कैसे?

कला समेकित शिक्षा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* के माध्यम से कला समेकित शिक्षा की संकल्पना को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थानों के शिक्षकों/शिक्षिकाओं को विभिन्न विषयों को कला (दृश्य और प्रदर्शनीय दोनों प्रकार की) के साथ

समेकित करके सृजनात्मक शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.सी.) द्वारा अंगीकृत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि कला, सिर्फ कला के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य विषयों को भी समझने और समझाने में बेहद उपयोगी है। कला समेकित शिक्षण में संगीत, ड्रामा और फ़िल्म-प्रदर्शन का प्रयोग शिक्षा के हर स्तर पर उल्लेखनीय योगदान कर सकता है। आशा की जा सकती है कि इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति, विज्ञान आदि विषय कला एवं सिनेमा के प्रयोग से आसान एवं रोचक ढंग से सीखे और सिखाए जा सकेंगे।

शिक्षा, इंटरनेट और डिजिटल इंडिया

बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में इंटरनेट के आविष्कार ने सिर्फ विज्ञान ही नहीं, बल्कि शिक्षा जगत में भी अभूतपूर्व क्रांति ला दी है। भारतीय शिक्षा जगत भी इससे अछूता नहीं रहा है। वर्ष 1995 में, भारतीय शिक्षण संस्थाओं को भी इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो चुकी थी। वर्तमान समय में यू.जी.सी. के अधीन कुल 907 विश्वविद्यालय हैं (31 मार्च, 2019 तक अद्यतित)। जिनमें अधिकतर उच्च-तकनीकी सेवाओं से लैस संस्थान बन चुके हैं। एक समय था जब गूगल, इनसाइक्लोपीडिया और विकिपीडिया शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों, शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए सबसे बड़े मददगार हुआ करते थे। आज विभिन्न सोशल प्लेटफ़ॉर्म, जैसे— यूट्यूब, एकेडेमिया.ओआरजी, जे स्टोर और कंप्यूटर व मोबाइल आधारित ऐप्स, जैसे— यूएन एकेडेमी, खान एकेडेमी, बाइजूस

आदि ने विद्यार्थियों को सारी अध्ययन सामग्री उनके मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप में ही समेट कर दे दी है। अब तो व्हाट्सएप, मैसेंजर, हाइक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ने भी पी.डी.एफ. और डॉक्यूमेंट फ़ाइलों का आदान-प्रदान करने वाली सुविधाएँ प्रदान की हैं जिससे पल भर में कोई भी डाटा कहीं भी भेजा जा सकता है। इन ऐप्स की गति और इंटरनेट सुविधाओं की सस्ती होती दरों ने ई-मेल को भी 'प्राचीन' बना दिया है। आज विद्यार्थी न केवल किसी भी विषय की कोई भी समस्या का हल इन वेबसाइटों और ऐप्स पर पा सकता है, बल्कि उन्हें हल करने के भिन्न-भिन्न तरीके भी सीख और समझ सकता है। इनकी सहायता से न केवल बच्चों अपितु शिक्षकों व शिक्षिकाओं की भी शिक्षण संबंधी कठिनाइयाँ कम हुई हैं। इससे समय की भी बचत होती है जिससे वे इससे स्वयं कुछ न कुछ नया सीखते रहने में अग्रसर रहते हैं।

वर्ष 1990 में सर टिम बर्नर्स ली द्वारा वर्ल्डवाइड वेब के आविष्कार के बाद से अब तक विज्ञान और तकनीक ने अभूतपूर्व तरक्की की है। कभी विद्यालय या कॉलेज के सभागार में लेक्चर अथवा सेमिनार सुनने जाना विद्यार्थियों में उत्सुकता की बात होती थी, वहीं अब 'सेमिनार' की जगह 'वेबिनार' और लेक्चर की जगह 'ऑडियो-विजुअल ट्यूटोरियल्स' ने ले ली है जिसे विद्यार्थी अपनी इच्छा और सुविधानुसार 'लाइव' या 'रिकार्डेड ब्रॉडकास्ट' स्ट्रीम कर सकते हैं। आज प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालयों तक में यह नवीन रूपांतरण देखा जा सकता है।

सूचना युग के दौर में भारतीय शिक्षा व्यवस्था अठारवीं सदी से 19वीं सदी के मध्य के समय को हम 'औद्योगिक युग' (द इंडस्ट्रीयल ऐज) के रूप में जानते हैं। जिसमें यूरोपियन द्वारा दुनिया भर में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों और कारखानों की स्थापना की गई और भाप इंजन, रेल आदि का आविष्कार हुआ। उसके बाद के 100 वर्षों को 'मशीन युग' (द मशीन ऐज) के नाम से जाना गया। जिसमें कैमरा, टी.वी., बल्ब, टाइपराइटर, बॉल पेन इत्यादि छोटी-बड़ी व खासकर बिजली से चलने वाली मशीनों का आविष्कार हुआ। इन आविष्कारों ने मानव जीवन स्तर को ऊँचा किया। मशीन युग के बाद 'सूचना युग' (द इन्फोर्मेशन आरंभ हुआ, जिसे 'डिजिटल युग' के नाम से भी जाना जाता है। सूचना युग के कारण आज हम दुनिया भर की हर जानकारी को चुटकियों में प्राप्त कर सकते हैं।

वर्तमान डिजिटल युग में, भारत सरकार के शिक्षा विभाग और साथ ही राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों ने 'समय के साथ चलने' की युक्ति को बखूबी समझा और आत्मसात किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'डिजिटलाइजेशन' को स्वीकारते हुए *स्वयं प्रभा* नाम से 32 डीटीएच चैनल आरंभ किए हैं। जिससे देश भर के लोग विभिन्न विषयों, जैसे— मानविकी, इंजीनियरिंग, कला, विधि आदि को टी.वी. पर किसी भी समय देखकर पढ़ और सीख सकते हैं। साथ ही राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एन.एस.पी.), राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एन.डी.एल.) और मेरी सरकार (माई गवर्नमेंट) जैसी ऑनलाइन सुविधाएँ विद्यार्थियों की सहायता

के लिए हर समय उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की ई-पाठशाला, इन्फो की स्टूडेंट-ऐप और एन.आई.ओ.एस. व केंद्रीय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के डिजिटल रूपांतर इस बात को साबित करते हैं कि किताबों का जो ज्ञान आज स्मार्टफोन, टेबलेट्स और क्लाउड लर्निंग में बदल चुका है, उस ज्ञान को हर भारतीय तक पहुँचाने में अब लगभग सभी शीर्ष शैक्षणिक संस्थाएँ भी 'डिजिटलाइजेशन' को माध्यम बना रही हैं।

अध्ययन-अध्यापन की पारंपरिक प्रक्रिया से डिजिटल प्रक्रिया में 'डिजिटलाइज' किए जाने का असर सिर्फ शिक्षक-शिक्षिकाओं और संस्थानों पर ही नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के केंद्र बिंदु, विद्यार्थियों और उनके प्रदर्शन पर भी उतना ही पड़ा है। पहले जो ज्ञान विदेशी भाषा में होने या पुस्तकालय में अनुपलब्ध होने अथवा 'महंगा' होने आदि कारणों से उनके अकादमिक प्रदर्शन को कमतर कर देता था, आज वह सारा ज्ञान और जानकारियाँ उन्हें यूपल भर में मिल जाती हैं। जिसका श्रेय पूर्ण रूप से सूचना-तकनीकी क्रांति को जाता है। इस डिजिटल क्रांति की सहायता से आज विद्यार्थी बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं, नई ऊँचाइयों को छू रहे हैं। आज विद्यार्थी अपने क्षेत्र, जिला, राज्य, देश, महाद्वीप के अतिरिक्त, यदि वे दूसरे ग्रह-उपग्रह आकाशगंगा अथवा ब्रह्मांड का भी अध्ययन करना चाहें तो डिजिटलाइजेशन की सहायता से सरलता से कर सकते हैं।

उपसंहार

“महान शक्तियों के साथ महान जिम्मेदारियाँ भी आती हैं”, युवाओं में मशहूर कॉमिक-फ़िल्मी

किरदार 'स्पाइडरमैन' के अंकल बेन पार्कर द्वारा कही गई यह बात शिक्षण क्षेत्र में नई तकनीकों के बढ़ते वर्चस्व पर भी लागू होती है। गुरुकुल के ताम्रपत्रों से निकली शिक्षा आज 8 गुणे 10 इंच के टैब्लेट में आसिमटी है। हालाँकि, इसकी सीमाएँ विचारों की तरह ही अनंत है और विचार ही तो इस नित नई अद्यतन होती तकनीकी का मुख्य आधार हैं।

एक ओर नई-नई तकनीकों ने विद्यार्थियों व शिक्षकों/शिक्षिकाओं को सीखने की असीम संभावनाएँ उनके पॉकेट में लाकर दे दी हैं, वहीं ये अपने साथ छद्म जानकारियों का इतना सारा 'ई-कूड़ा' लाती जा रही हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क सही व व्यर्थ डेटा में फ़र्क करना भूलता जा रहा है। आज बहुत-से विद्यार्थी व शिक्षक/शिक्षिका बिना तथ्यों की सत्यता जाँचे बस बहस करने को तत्पर होते जा रहे हैं। सिर्फ़ इस भरोसे कि इंटरनेट और तकनीकी से कहीं न कहीं से कैसे भी उनके तथ्यों को साबित करने के लिए 'डेटा' ले ही आएँगे। तकनीकी का अत्यधिक प्रयोग और उनके प्रति सीमा से अधिक निर्भरता, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिभागियों को तर्क-वितर्क के बजाय कुतर्क करने की आदत के हवाले करता जा रहा है। दूसरी ओर, तकनीकी शिक्षकों व शिक्षिकाओं की भी चुनौतियाँ दिन-प्रतिदिन बढ़ाती जा रही हैं, क्योंकि आज हर जानकारी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर तुरंत उपलब्ध है, जिससे विद्यार्थियों की 'क्रॉस-क्वेश्चनिंग' का जवाब देना उनके लिए कठिन होता जा रहा है। अतः आवश्यक है कि शिक्षक/शिक्षिकाएँ भी पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों के साथ डिजिटल तकनीकों से भी

समन्वय स्थापित करें और दोनों में परस्पर संतुलन बनाए रखें। इससे न केवल शिक्षक/शिक्षिका व विद्यार्थी समय के साथ स्वयं को अद्यतित या अपडेटेड रख पाएँगे, बल्कि पुस्तकों के साथ भी उनका जुड़ाव बना रहेगा। भले ही वह लगाव उसके डिजिटल प्रारूप अर्थात् पी.डी.एफ़. फ़ॉर्मेट में ही क्यों न हो और इसी प्रकार हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलती तकनीकी और समय के साथ अप-टू-डेट होकर प्रसारित होती जाएगी।

भारतीय शिक्षा की प्राचीन काल से ही संपूर्ण विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान और गरिमा रही है। यह सदा वैज्ञानिक सोच और तार्किक बुद्धि से चली है, जिसमें कला एक अभिन्न अंग रही है। समय के साथ इसने अपने अंदर बहुत-से परिवर्तनों को आत्मसात किया है, फिर चाहे वह किसी अन्य सभ्यता की शैली हो या शब्द-विन्यास-भाषा इत्यादि। बहुत-से विचारकों के अथक परिश्रम के बाद यह लगभग प्रत्येक नागरिक तक पहुँचने में सफल रही है और इसमें इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के योगदान को श्रेय देना नैसर्गिक है। आज इसी तकनीक की मदद से शिक्षा जन-जन तक पहुँची है। कहते हैं कि तकनीक अपनी ओर से तटस्थ होती है, सकारात्मकता और नकारात्मकता उसे प्रयोग करने वाले मनुष्य पर निर्भर करती है। आज जो व्यक्ति स्कूल-कॉलेज नहीं जा पाता, वह भी मोबाइल पर पढ़ना सीख लेता है। लोग अकसर इल्ज़ाम लगाते हैं कि स्कूल, बच्चों की सृजनशक्ति को कमजोर अथवा समाप्त कर देते हैं, क्योंकि शिक्षक/शिक्षिका उन्हें केवल अपने

अनुसार कार्य करने को बाध्य करते हैं न कि बच्चों की इच्छानुसार! क्या यह शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षक/शिक्षिकाओं का दायित्व नहीं बनता कि वह विद्यार्थियों को स्वतंत्र भाव से सीखने का समान अवसर प्रदान करें? डिजिटल शिक्षा के भविष्य की बात करें तो आने वाले 10-15 वर्षों में संभव है कि स्कूली बच्चे भी 'स्कूल-बैग' से पूर्णतः मुक्त हो जाएँ और उनके सभी कक्षा कार्य,

गृह कार्य, प्रोजेक्ट इत्यादि क्लाउड-स्टोरेज में 'सेव और एक्सेस' किए जा सकें। यह भी संभव है कि भविष्य में पारंपरिक भौतिक/इमारती शैक्षणिक संस्थानों का स्थान होलोग्राफिक और वर्चुअल प्रोजेक्शन आधारित 'ओपेन एयर थिएटर' ले लें, जैसे— कभी प्राचीन रोम के कोलोजियम अथवा भारतवर्ष के गुरुकुल की व्यवस्था थी, संभव है कि इस भविष्य का आधार हमारे अतीत में ही मिलेगा।

संदर्भ

वर्मा, सुभाष. 2004. *भारत में शिक्षा व्यवस्था— अवधारणाएँ, समस्याएँ एवं संभावनाएँ*. वाणी प्रकाशन, दिल्ली.

भारतीय विश्वविद्यालयों की समेकित सूची. <https://www.ugc.ac.in/oldpdf/Consolidated%20list%20of%20All%20Universities.pdf> से लिया गया है.

“द पॉवर ऑफ़ डिजिटल लर्निंग”. *इंटरप्रिन्योर* पर परिणीता गोहिल द्वारा 23 नवंबर, 2018 को प्रकाशित ऑनलाइन लेख. <https://www.entrepreneur.com/article/323708> से लिया गया है.